

Uncorrected/Not for publication - 20.08.2010

MKS-GS/11.30/1G

प्रश्न संख्या : 384

U.N. Mehta  
 (U. N. MEHTA)  
 अवर सचिव (संयुक्त)  
 Under Secretary (Part.)  
 रेल मंत्रालय  
 Ministry of Railway  
 रेलवे बोर्ड  
 Railway Board  
 नई दिल्ली / New Delhi

**श्री नंद कुमार साय :** माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से जीपीएस के संबंध में पूछा था। यह परियोजना रेल सुरक्षा के लिए तकनीकी मिशन के तहत 2003 में स्वीकृत की गई थी और इसको 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य था। किन्तु राजधानी या शताब्दी जैसी कुछ ट्रेन्स हैं, 40-50 ट्रेनों में ही यह सिस्टम लगाया जा सका है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 से 2010 तक सात वर्षों में इतनी कम ट्रेनों में इसको लगाया गया है, इसमें विलम्ब बहुत हुआ, उसके क्या कारण हैं ? क्या इसको और भी जगह लगाने के लिए कोई योजना रेल मंत्रालय के पास है ?

**कुमारी ममता बत्तजी :** सर, जीपीएस सिस्टम को यू.एस. में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो रेलवे की एक्सपर्ट्स कमेटी Sam Pitroda की है, उन्होंने रिकमंडेशन दी, for SIMRAN and it is under consideration. We will do it as early as possible. From the safety point of view, हम लोगों ने जो pilot projects किया था, उसको हमने <sup>₹ 3.5 करोड़</sup> 42 लाख में किया था और अब यह complete हो गया है, यह successful हुआ है, and SIMRAN will be helpful in preventing the accidents even from the unmanned level crossings. So, we have decided to do it immediately and it will be completed within two years, Sir.

**श्री सभापति :** आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

**श्री नंद कुमार साय :** माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि RDSO और IIT कानपुर SIMRAN के माध्यम से दो नये उपाय रेल पथों पर गैंगमेन और ट्रैकमेन की चेतावनी देने के हैं और दूसरे में चौकीदार रहित, सहित समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए परीक्षण कर रहे हैं। क्या इन उपायों को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है ? यदि कोई समय-सीमा तय की गई है, तो उसको पूरा करने के लिए कब तक समय-सीमा है ?

Uncorrected/Not for publication - 20.08.2010

Q. No.384 (Contd.)

**कुसारी ममता बनर्जी** : सर, मैंने बताया था कि दो साल में यह कम्पलीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन SIMRAN के बारे में है, जो कानपुर IAT ने किया था, जिस पर रेलवे मिनिस्ट्री ने और HRD मिनिस्ट्री ने काम किया था, वह सक्सैसफुल हो गया है और वह दो साल में कम्पलीट हो जाएगा।

**श्री सभापति** : श्री मोहम्मद अमीन।

**SHRI MOHAMMED AMIN**: Sir, there are a large number of vacancies in the Railways. Connected with the question of railway safety, I want to know from the hon. Minister.....(Interruptions)...

**MR. CHAIRMAN**: The question is on GPS in railways.

**श्री मोहम्मद अमीन** : सर, रेलवे का ही तो मामला है।

**श्री सभापति** : नहीं, यह जीपीएस के संबंध में है।

**श्री मोहम्मद अमीन**: सर, इसमें एक्सीडेंट का सवाल है और एक्सीडेंट का रेलवे सेफ्टी के साथ कनेक्शन है।

**MR. CHAIRMAN**: No, no; railway safety is a much wider subject. Let us confine the supplementary to the main question, please.

**श्री मोहम्मद अमीन** : सर, हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जो वेकेंसीज़ खाली हैं, इनके लिए पिछले छह महीने में कितने लोगों को लिया गया है and by what time these vacancies will be filled up.

**MR. MAMATA BANERJEE**: This is, absolutely, a different question, Sir. This is about equipment. The main question relates to GPS. But, for my friend, I want to say that already, we have started. We have started the work; the process is on. Because for ten years it was not done, the vacancy was there. This time, we

Uncorrected/Not for publication - 20.08.2010

Q. No.384 (Contd.)

have started the process of filling the vacancies, and we are giving the special (diet) for SCs/STs, Physically Handicapped and the Minorities, and we are giving them the priority. As for OBCs and Disabled Persons, I have already covered. Then, for the Sports quota.....

**MR. CHAIRMAN:** Thank you.

**KM. MAMATA BANERJEE:** And the drive is on. We have done as per the new recruitment policy, and the process is on.

**MR. CHAIRMAN:** Thank you. Shrimati Shobhana Bhartia.

**SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:** Thank you, Sir. About the GP System, that would give real time information, there are certain concerns about the security, that this information can be used and misused by those who want to get the actual position and those who want to destroy and sabotage the railway tracks, and all that. In view of the fact that there have been certain suspected sabotage incidents and the consequent loss of life, what inbuilt checks and balances would the Ministry propose to keep so that this flow of information is not misused to actually damage the railway tracks?

**KM. MAMATA BANERJEE:** Sir, I am really obliged because Shobhana Bhartiya has raised a very valid question. Yes, there is a concern, and we are examining it in detail; that is why some time more we are taking. But let me assure the House that we have to do it very quietly because the country matters; if there is a matter of security, it is a concern for each and every one. For that, we are trying to do

focus  
NIM (as MS)

ML

Uncorrected/Not for publication - 20.08.2010

Q. No.384 (Contd.)

something. We will talk to the other Ministries, and also to the concerned Ministry, and we will take full precautions.

(Contd. by TMV/1H)

MKS-TMV-ASC/1H/11.35

**MAMATA BANERJEE (CONTD.):** Nowadays, in the Railways, sabotage and terrorism are so much. They were not there earlier. The Railways is for the people. Earlier it was only protesting, अब तो सबोटेज के लिए भी हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम भी हो गई है। She has raised a very valid point. We will get the details. We will examine the case very seriously. If there is any need for some foolproof security system, we will consider it and then we will do it.

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी :** सर, मैं मानीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हम GPS सिस्टम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। रेलवे की जो लाइनें हैं और उनके ऊपर जो फ्लाई ओवर बनते हैं, उनमें से काफी फ्लाई ओवर बनकर तैयार हैं। रेलवे लाइन के ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसको रेलवे को तैयार करना होता है तथा यह उसकी जिम्मेवारी भी है, लेकिन वह अधूरा पड़ा हुआ है। ..(व्यवधान)..

**श्री सभापति :** यह GPS का सवाल है।

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी :** सर, यह इन्फोर्मेशन ही है। GPS के माध्यम से रेल की इन्फोर्मेशन देनी है, तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर के माध्यम से पुल की इन्फोर्मेशन ले लेंगे।

**श्री ममता बनर्जी :** सर, मैं कोई A to Z dictionary नहीं हूँ। यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। स्टेट गवर्नमेंट फ्लाई ओवर के लिए 50 परसेंट देती है और रेलवे भी 50 परसेंट देती है। इस बारे में हमारा जो काम था, वह हमने पूरा कर दिया है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कम्प्लेंट है, तो you can write to me, and I will give you the details.

(Ends)

MM/asms